

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री छगनलाल गोयल,  
आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या

30/2018

अपीलांत	बनाम	रेस्पोजेन्ट
कानसिंह पुत्र अखेसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी माण्डवला, तहसील व जिला जालोर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956  
विरुद्ध आदेश तहसीलदार जालोर, दिनांक 20.8.2018 (प्रकरण सं.50/18)

उपस्थिति :-

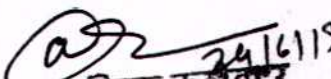
1. श्री चुन्नीलाल पुरोहित, अभिभाषक, अपीलांत की ओर से।
2. श्री छोट्टसिंह, सरकारी अभिभाषक, रेस्पोजेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 24.6.2019

1. अपीलांत के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का माण्डवला के आधार पर तहसीलदार जालोर द्वारा अपीलांत को संवत् 2075 में खसरा नम्बर 437 रकबा 1.20 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन पर रकबा 0.4 हेक्टर भूमि पर कब्जा, पक्का कमरा का अतिक्रमण मानते हुए प्रकरण सं. 50/18 दर्ज कर, नोटिस जारी कर, आबाद मकान पर चस्पानगी बताते हुए तामील मानकर दिनांक 20.8.2018 को बेदखली व जुर्माना का आदेश दिया है। आदेश 6 सी.पी.सी.के अन्तर्गत चस्पानगी न्यायालय के आदेश से ही हो सकती है। दिनांक 23.7.18 को उत्तमसिंह की उपस्थिति बताते हैं तथा साक्ष्य, सबूत हेतु पत्रावली रखी जाती है। उत्तमसिंह प्रकरण में पक्षकार नहीं है, उनके खिलाफ कोई नोटिस नहीं है, अदालत मातहत द्वारा उत्तमसिंह की तामील मानकर जवाब व सबूत के लिए अवसर दिया जबकि अपीलांत को मुकदमें की जानकारी नहीं थी, पत्रावली दिनांक 6.8.18 को रखी गई, दिनांक 6.8.18 को अपीलांत की पुत्री जो विवाहित है, उसकी उपस्थिति बताकर, आदेश हेतु दिनांक 20.8.18 को रखी गई, दिनांक 20.8.18 को पत्रावली में अपीलांत को अनुपस्थित बताकर मौके पर बेदखल व जुर्माना के आदेश दिये गये। न्यायालय द्वारा अपीलांत के धारा 91 के कानून के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई, न तो अपीलांत को नोटिस दिया एवं न ही अपीलांत उपस्थित हुआ, न ही अपीलांत को गवाह, सबूत पेश



  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
जालोर (राज.)

करने का अवसर दिया। न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. की पालना नहीं की गई है। अपीलांत का विवादग्रस्त भूमि पर कई वर्षों से कब्जा है। ग्राम पंचायत माण्डवला द्वारा सन् 1991 में भी इस भूमि के संबंध में कब्जे के प्रमाण पत्र दिये हुए थे। यह भूमि आबादी में आई हुई है, केवल मात्र सैटलमेन्ट की गलति से गैर मुमकिन दर्ज की गई जबकि पंचायत माण्डवला द्वारा सन् 1998 में भी इस भूमि के संबंध में प्रमाण पत्र जारी किये हुए हैं। अपीलांत उक्त भूमि पर मवेशी बांध रहा था, मौके पर जलाउ लकड़ी, पत्थर आदि पड़े हुए हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.8.2018 निरस्त करावे तथा अपीलांत को सुनवाई का आदेश देते हुए पुनः आदेश दिलावे। अपीलांत ने अपील में फहरिस्त के साथ निर्णय दिनांक 20.8.18 आदि की नकले पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोंडेंट को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. प्रार्थी रूपाराम पुत्र रतनाजी, जाति चौधरी, निवासी माण्डवला ने इसमें पक्षकार बनाने हेतु दिनांक 23.8.18 को प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश किया जो बाद सुनवाई के दिनांक 18.9.2018 को खारिज किया गया।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांत के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि अपीलांत का परिवार बाहर गांव में रहता है, घर बंद है, घर पर कोई व्यक्ति हाजिर नहीं है, अदालत मातहत ने नोटिस चस्पानगी बताते हुए तामील मानी जाकर कार्यवाही की गई है, दिनांक 10.8.17 को मुकदमा दर्ज किया, दिनांक 23.7.18 को पेशी पर उत्तमसिंह की उपस्थिति बताई है जबकि इस प्रकरण में उत्तमसिंह पक्षकार नहीं था, इसमें साक्ष्य सबूत हेतु अवसर देकर पेशी 6.8.18 रखी गई, दिनांक 6.8.18 को अपीलांत की पुत्री की उपस्थिति बताकर आगामी पेशी 20.8.18 को रखी गई, दिनांक 20.8.18 को अपीलांत की अनुपस्थिति बताकर मौके से बेदखली व जुमाने का आदेश दिया गया है, आदेश 6 सी.पी.सी. के अन्तर्गत चस्पानगी न्यायालय के आदेश से ही हो सकती है। अपीलांत का विवादग्रस्त भूमि पर कई वर्षों से कब्जा है इस संबंध में ग्राम पंचायत ने वर्ष 1991, 1998 में कब्जे के प्रमाण पत्र दिये हैं, यह भूमि आबादी में आई हुई केवल मात्र सैटलमेन्ट की गलति से यह भूमि गैर मुमकिन दर्ज की गई, अतः अपीलांत की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.8.18 निरस्त करावे। इसके विपरीत रेस्पोंडेंट की ओर से सरकारी वकील ने बताया कि अपीलांत कानसिंह द्वारा संवत् 2075 में माण्डवला के खसरा नम्बर 437 रकबा 1.20 हेक्टर किस्म गैर



आदेश दिनांक 24/11/18  
जालोर (राज.)

मुमकिन भूमि में से 400 वर्ग मीटर पर कब्जा कर पक्का कमरा बनाने से तहसीलदार जालोर द्वारा दिनांक 20.8.18 को बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया गया है, भूमि की किस्म गैर मुमकिन यानि राजकीय भूमि होने से आदेश सही पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट कानसिंह द्वारा संवत् 2075 में माण्डवला के खसरा नम्बर 437 रकबा 1.20 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि में से 400 वर्ग मीटर पर कब्जा कर पक्का कमरा बनाने से पटवारी हल्का माण्डवला की रिपोर्ट जिसको भू अभिलेख निरीक्षक माण्डवला द्वारा जांच की गई है, अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जालोर को पेश करने पर प्रकरण सं. 50/18 दिनांक 10.7.18 को दर्ज किया जाकर, अपीलांट को नोटिस जारी किया गया जिसकी आगामी तारीख पेशी 23.7.18 को रखी गई, दिनांक 23.7.18 को गैर सायल की ओर से श्री उत्तमसिंह पुत्र हेमसिंह रा.राजपूत, निवासी सायला जो गैरसायल का जवाई लगता है, उपस्थित हुआ व उसको साक्ष्य, सबूत हेतु अवसर दिया जाकर आगामी तारीख पेशी 6.8.18 को दी गई, दिनांक 6.8.18 को अपीलांट की पुत्री बसंती अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुई है जिसको साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर दिया तथा आयन्दा पेशी पर दिनांक 20.8.2018 दी गई, दिनांक 20.8.2018 को बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया गया है।



सवार श्री रामलाल, कार्यालय तहसीलदार जालोर की रिपोर्ट अनुसार आसामी ने तारीख पेशी 23.7.18 का नोटिस लेने से इन्कार करने पर, आसामी के खुले मुकान पर दो मौतबिरान के रूबरू चस्था किया गया है। आदेश 5 रूल 17 अनुसार " जहां प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है, या जहां तामील करने वाला अधिकारी सभी सम्यक् और युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात् ऐसे प्रतिवादी को न पा-सके (जो अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित है, जब उस पर समन की तामील उसे निवास स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाये जाने की संभावना नहीं है) और ऐसे कोई अभिकर्ता नहीं है जो समन की तामील का प्रतिग्रहण उसकी ओर से करने के लिए सशक्त है और न कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर तामील की जा सके, वहां तामील करने वाला अधिकारी उस गृह के, जिसमें प्रतिवादी मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर समन की एक प्रति लगाएगा और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ, जिसमें यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसा लगा दिया है

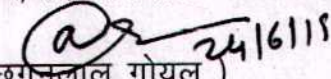
और वे कौनसी परिस्थितियां थी जिनमें उसने ऐसा किया, कथित होगी और जिसमें उस व्यक्ति का (यदि कोई हो) नाम और पता कथित होगा जिसने गृह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी, उस न्यायालय को लौटाएगा जिसने समन निकाला था।" उपरोक्तानुसार सवार, तहसील कार्यालय जालोर अनुसार कानसिंह द्वारा नोटिस लेने से इन्कार करने पर नोटिस आसामी के खुले मकान पर दो मौतबिरान् के रूबरू चस्पा किया गया है जो तामील की परिभाषा में आता है।

इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी 6.8.2018को पेशी पर अपीलांट-कानसिंह की पुत्री बसंती भी उपस्थित हुई है इससे हम यह नहीं मान सकते कि अपीलांट को इस प्रकरण बाबत जानकारी नहीं है एवं साक्ष्य, सबूत का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर लगातार कब्जा के संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किये है जिससे उसका अतिक्रमण नियमन की परिभाषा में भी नहीं आता है। भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर यानि सरकारी भूमि होने से तहसीलदार जालोर द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है।

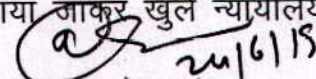
अपीलांट वकील ने भी इस भूमि बाबत किसी भी न्यायालय में कोई स्थगन होने का साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

आदेश

अपीलांट द्वारा तहसीलदार जालोर के आदेश दिनांक 20.8.2018 (प्र.सं.50/18) के विरुद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल सुदा मानी जाकर, नम्बर से कम होकर, बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ़्तर दाखिल हो।

  
(छगनलाल गोयल)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
जालोर (राज.)

निर्णय, आज दिनांक 24.6.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

  
(छगनलाल गोयल)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
जालोर (राज.)